



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2015/पौष 16, 1936

No. 46] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2015/PAUSA 16, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 52(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “वरदान सेवा संस्थान बी-46, नेहरू अपार्टमेंट, नेहरू नगर-3, गाजियाबाद” द्वारा “वरदान मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 9.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 14 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “वरदान सेवा संस्थान बी-46, नेहरू अपार्टमेंट, नेहरू नगर-3, गाजियाबाद” द्वारा चलाई जा रही “वरदान मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल” की परियोजना अथवा स्कीम को 9.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 01/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 52(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, “Vardan Multispecialty Hospital” by “Vardan Sewa Sansthan, B-46, Nehru Apartments, Nehru Nagar-3, Ghaziabad”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.9.30 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Vardan Multispecialty Hospital”, which is being carried out by “Vardan Sewa Sansthan, B-46, Nehru Apartments, Nehru Nagar-3, Ghaziabad”, without any change in the approved cost of Rs.9.30 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 01/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 53(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 05-07-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 998 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “रावल माली-नाथजी फाउन्डेशन, जसोल हाउस, पओटा, बी-4, जोधपुर-342010, राजस्थान” द्वारा “डे केयर हॉस्पिटल एंड मोबाइल रूरल आउटरीच प्रोग्राम” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए 9.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तीन और वर्षों के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 766(अ), दिनांक 18-03-2011 द्वारा और बढ़ाया गया था; जिसे वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 466(अ), दिनांक 16-3-2012 द्वारा और आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के

उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “रावल मालीनाथजी फाउन्डेशन, जसोल हाउस, पओटा, बी-4, जोधपुर-342010, राजस्थान” द्वारा चलाई जा रही “डे केयर हॉस्पिटल एंड मोबाइल रूरल आउटरीच प्रोग्राम” की परियोजना अथवा स्कीम को 9.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 02/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 53(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated 05.07.2006 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Day care hospital and mobile hospice rural outreach programme” by “Rawal Mallinathji Foundation, Jasol House, Paota B-4, Jodhpur – 342010 Rajasthan”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.9.78 crore for a period of two years ending with financial 2007-08; which was further extended vide notification number S.O. 766(E) dated 18.03.2011 for three more years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 464(E) dated 16.3.2012 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 8 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Day care hospital and mobile hospice rural outreach programme”, which is being carried out by “Rawal Mallinathji Foundation, Jasol House, Paota B-4, Jodhpur-342010, Rajasthan”, without any change in the

approved cost of Rs.9.78 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 2/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 54(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 03-02-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 135 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “महावीर इंटरनेशनल, 6550, मेन कुतब रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055” द्वारा “डाक्टर एट डोरस्टेप” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2005, 2006-07 और 2007-08 के लिए 2.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; और जिसे वर्ष 2008-09 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 तक अधिसूचना सं. का.आ. 237(अ), दिनांक 21-01-2009 द्वारा और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 870(अ), दिनांक 27-4-2011 द्वारा और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना सं. का.आ. 135(अ), दिनांक 3-2-2006 को संशोधित करके अधिसूचना सं. का.आ. 870(अ), दिनांक 27-4-2011 द्वारा परियोजना लागत को ‘2.40 करोड़; रुपए’ से बढ़ाकर ‘8.40 करोड़ रुपए’ किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “महावीर इंटरनेशनल, 6550, मेन कुतब रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055” द्वारा चलाई जा रही “डाक्टर एट डोरस्टेप” की

परियोजना अथवा स्कीम को 8.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 03/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 54(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 135(E) dated 03.02.2006 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, “Doctor at Doorstep” by “Mahavir International, 6550, Main Qutab Road, Nabi Karim, New Delhi 110055”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.40 crore for a period of three years i.e., 2005-06, 2006-07 and 2007-08; which was further extended vide S.O. No.237(E) dated 21.01.2009 for a period of three financial years commencing with 2008-09 i.e., 2008-09, 2009-10 & 2010-11; and which was further extended vide Notification number S.O. 870(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas vide Notification number S.O. 870(E) dated 27.4.2011 the project cost was enhanced from ‘Rs.2.40 crore’ to ‘Rs.8.40 crore’ by amending the notification number S.O. 135(E) dated 03.02.2006;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Doctor at Doorstep”, which is being carried out by “Mahavir International, 6550, Main Qutab Road, Nabi Karim, New Delhi 110055”, without any change in the approved cost of Rs.8.40 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 3/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 55(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 06-08-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “आनंद आश्रम सेवा ट्रस्ट, सम्पया, दार्ने डाकखाना पुत्तूर, (दक्षिण कन्नड़), कर्नाटक-574202” द्वारा “आनंद आश्रम-स्वामि-ए वार्ड- “प्रशांति” प्रशामक (होसपाइस), वृद्ध और टर्मिनली बीमार कैंसर रोगियों के लिए देखभाल गृह” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 16-3-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ), द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “आनंद आश्रम सेवा ट्रस्ट, सम्पया, दार्ने डाकखाना पुत्तूर, (दक्षिण कन्नड़), कर्नाटक-574202” द्वारा चलाई जा रही “आनंद आश्रम-स्वामि-ए वार्ड- “प्रशांति” प्रशामक (होसपाइस) वृद्ध और टर्मिनली बीमार कैंसर रोगियों के लिए देखभाल गृह” की परियोजना अथवा स्कीम को 4.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 04/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 55(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2033 (E) dated

6.08.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, “Anandashram –Smile a while- “Prashanthi” A palliative (Hospice), care home for the aged and terminally ill cancer patients” by “Anandashram Seva Trust, Sampya, Darne PO Puttur, (Dakshina Kannada), Karnataka –574202”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 4 crore for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 461(E) dated 16.3.2012 for a period of three years commencing with the financial year 2011-12, i.e., 2011-12, 2012-13 and 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Anandashram –Smile a while- “Prashanthi” A palliative (Hospice), care home for the aged and terminally ill cancer patients”, which is being carried out by “Anandashram Seva Trust, Sampya, Darne PO Puttur, (Dakshina Kannada), Karnataka-574202”, without any change in the approved cost of Rs.4 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 4/2015 /F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 56(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 06-08-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “आनंद आश्रम सेवा ट्रस्ट, सम्पया, दार्ने डाकखाना पुत्तूर, (दक्षिण कन्नड़), कर्नाटक-574202” द्वारा “आनंद आश्रम-स्वामि-ए वार्ड- “प्रशांति” प्रशामक (होसपाइस), वृद्ध और टर्मिनली बीमार कैंसर रोगियों के लिए देखभाल गृह” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 16-3-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ), द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि

अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “आनंद आश्रम सेवा ट्रस्ट, सम्पया, दार्ने डाकखाना पुतूर, (दक्षिण कन्नड़), कर्नाटक-574202” द्वारा चलाई जा रही “आनंद आश्रम-स्वमाइल-ए वाईल- “प्रशांति” प्रशामक (होसपाइस) वृद्ध और टर्मिनली बीमार कैंसर रोगियों के लिए देखभाल गृह” की परियोजना अथवा स्कीम को 4.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 05/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 56(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O 121(E) dated 12.01.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 21, “Nanaksar Dashmesh Public School” by “Anand Isher Educational Charitable Trust, Chhappar Road, Village Chhappar, Ahmad Garh, Mandi, Ludhiana, Punjab”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.18.51 crore for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide Notification number S.O. 1393(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project

or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Nanaksar Dashmesh Public School”, which is being carried out by “Anand Isher Educational Charitable Trust, Chhappar Road, Village Chhappar, Ahmad Garh, Mandi, Ludhiana, Punjab”, without any change in the approved cost of Rs.18.51 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 5/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 57(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23-12-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “विश्व प्रतिष्ठान, घर सं. 735/23, दीनदयाल नगर, कुरुडुवाडी रोड, बार्शी, तल-बार्शी, जिला सोलापुर-413401, महाराष्ट्र” द्वारा “दूसरी पारी गृह-ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था गृह” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 52.87 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 180.33 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 14 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “विश्व प्रतिष्ठान, घर सं. 735/23, दीनदयाल नगर, कुरुडुवाडी रोड, बार्शी, तल-बार्शी, जिला सोलापुर-413401, महाराष्ट्र” द्वारा चलाई जा रही “दूसरी पारी गृह-ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था गृह” की परियोजना अथवा स्कीम को 52.87 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 180.33 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14,

2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगी।

[सं. 06/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 57(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021 dated 23.12.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, “SECOND INNING HOME - Old Age Home for Senior Citizens in Rural Areas” by “Vishwa Pratishthan, Ghar No.735/23, Dindayal Nagar, Kurduwadi Road, Barshi, Tal-Barshi, Dist-Solapur – 413401. Maharashtra”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.180.33 lakh including corpus fund of Rs.52.87 lakh for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “SECOND INNING HOME - Old Age Home for Senior Citizens in Rural Areas”, which is being carried out by “Vishwa Pratishthan Ghar No.735/23, Dindayal Nagar, Kurduwadi Road, Barshi, Tal-Barshi, Dist-Solapur – 413401. Maharashtra”, without any change in the approved cost of Rs.180.33 lakh including corpus fund of Rs.52.87 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption under Section 35AC shall be available for the said financial year 2013-14.

[No. 06/2015/F.No.V. 27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 58(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5-04-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 49-50, रेड क्रॉस हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली” “क पश्चिमी भारत रेन फैंड फार्मिंग परियोजना, ख पूर्वी भारत रेन फैंड फार्मिंग परियोजना” की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2005-06 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 9 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 26-10-2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1834(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 18-5-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1253(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 16-3-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 471(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1469(अ), द्वारा परियोजना लागत को 5.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए किया गया था; और जिसे दिनांक 16-3-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 471(अ) द्वारा 5.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 16 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए किया गया था।

और जबकि परियोजना लागत के ‘8 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए’ से बढ़कर ‘10.5 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए’ होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को ‘8 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए’ से बढ़कर ‘10.5 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए’ की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ) (अधिसूचना सं.का.आ. 1469(अ), दिनांक 17-6-2008 और का.आ. 471(अ),

दिनांक 16-3-2012 के साथ पठित) को निम्नलिखित प्रभाव के लिए संशोधित करती है, नामतः

‘उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम सं. (10), कालम (4) में, “8 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए” अक्षरों, अकों और शब्दों के लिए “10.5 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए” अक्षरों, अकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।’

[सं. 7/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 58(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.461(E) dated 5.04.2004 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “A. Western India Rainfed farming project, B. Eastern India Rainfed farming project” by “Gramin Vikas Trust, 49-50, Red Cross House, Nehru Place, New Delhi”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 9 crore for a period of three years ending with financial year 2005-06; which was further extended vide notification S.O.1834(E) dated 26.10.2006 for three more years ending with financial year 2008-09; which was further extended vide notification number S.O.1253 (E) dated 18.05.2009 for three more years ending with financial year 2011-12; and which was further extended vide notification number S.O. 471(E) dated 16.3.2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas vide notification number S.O. 1469(E) dated 17.06.2008, the project cost was enhanced from Rs.9 crore to Rs.16 crore including a corpus fund of Rs.5.00 crore; and which was further enhanced vide notification number S.O. 471(E) dated 16.3.2012 from Rs.16 crore including a corpus fund of Rs.5.00 crore to Rs.29 crore including a corpus fund of Rs.8 crore.

And whereas the project cost is likely to enhance from ‘Rs.29 crore including a corpus fund of Rs. 8 crore’ to ‘Rs.29 crore including a corpus fund of Rs.10.5 crore’;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from ‘Rs.29 crore including a corpus fund of Rs. 8 crore’ to ‘Rs.29 crore including a corpus fund of Rs.10.5 crore’.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax

Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.461(E) dated 5.04.2004 [read with notification numbers S.O.1469(E) dated 17.06.2008 and S.O. 471(E) dated 16.3.2012], to the following effect, namely:-

‘In the said notification, in the Table against serial number (10), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.29 crore including a corpus fund of Rs. 8 crore”, the letters, figures and words “Rs.29 crore including a corpus fund of Rs.10.5 crore” shall be substituted’.

[No. 7/2015 / F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 59(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14-06-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “टूथ ऑफ यूनीवर्स सोसायटी, 140, 141 अमृत कौर मार्किट, पहाड़ गंज, नई दिल्ली” द्वारा “मोबाइल प्रयोगशाला-सह-चिकित्सालय” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “टूथ ऑफ यूनीवर्स सोसायटी, 140, 141 अमृत कौर मार्किट, पहाड़ गंज, नई दिल्ली” द्वारा चलाई जा रही “मोबाइल प्रयोगशाला-सह-चिकित्सालय” की परियोजना अथवा स्कीम को 5.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 8/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 59(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, “Mobile Lab-cum-Clinic” by “Truth of Universe Society, 140,141 Amrit Kaur Market, Pahar Ganj, New Delhi”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.5.60 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Mobile Lab-cum-Clinic”, which is being carried out by “Truth of Universe Society, 140,141 Amrit Kaur Market, Pahar Ganj, New Delhi”, without any change in the approved cost of Rs.5.60 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 8/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 60(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6-06-1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 339 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “दारदिओनु राहत फंड, 102, काशी पारिख काम्प्लैक्स, 29, आदर्श सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009” द्वारा “चिकित्सा राहत परियोजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 137.08 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11-05-1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 312(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के

लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 7-06-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 608(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 4-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1317(अ) द्वारा तीन वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27-4-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 866(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत को दिनांक 19-4-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 510(अ) द्वारा “137.8 लाख रुपए” से ‘157.08 लाख रुपए’ तक बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 14-11-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1601(अ) द्वारा ‘157.08 लाख रुपए’ से ‘229.08 लाख रुपए’ तक बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 4-6-2008 अधिसूचना सं. का.आ. 1317(अ) द्वारा ‘229.08 लाख रुपए’ से ‘324.08 लाख रुपए’ तक और बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 27-04-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 866(अ) द्वारा ‘324.08 लाख रुपए’ से ‘454.08 लाख रुपए’ तक बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 454.08 लाख से बढ़कर 724.00 लाख रुपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को ‘454.08 लाख रुपए’ से बढ़ाकर ‘724.00 लाख रुपए’ करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “दारदिओनु राहत फंड, 102, काशी पारिख काम्प्लैक्स, 29, आदर्श सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009” द्वारा चलाई जा रही “चिकित्सा राहत परियोजना” या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और (ii) दिनांक 6-06-1996 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 339(अ) को अधिसूचना सं. का.आ. 510(अ), दिनांक 19-4-2004, का.आ. 1601(अ), दिनांक

14-11-2005, का.आ. 1317(अ), दिनांक 4-6-2008 और का.आ. 866(अ) दिनांक 27-4-2011 के साथ पठित निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (10), कालम (4) में, “454.08 लाख रुपए” अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए “724.00 लाख रुपए” अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 09/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 60(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 399(E) dated 6.6.96 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, “Medical relief project” by “Dardionu Rahat Fund, 102, Kashi Parekh Complex, 29, Adarsh Society, Navrangpura, Ahmedabad-380009”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.137.08 lakh for a period of three years ending with financial year 1998-1999; which was extended further vide notifications No. S.O. 312(E) dated 11.5.99 for three years ending with financial year 2001-02; which was further extended vide notification number S.O. 608(E) dated 7.6.2002 for a period of three years ending with financial year 2004-05; which was further extended vide notification number S.O. 1601(E) dated 14.11.2005 for three years ending with financial year 2007-08; which was further extended vide notification number S.O.1317(E) dated 4.06.2008 for three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 866(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the project cost was enhanced vide notification number S.O. 510(E) dated 19.4.2004 from ‘Rs.137.08 lakh’ to ‘Rs.157.08 lakh’; which was further enhanced vide notification number S.O. 1601(E) dated 14.11.2005 from ‘Rs.157.08 lakh’ to ‘Rs.229.08 lakh’; which was further enhanced vide notification number S.O.1317(E) dated 4.6.2008 from ‘Rs.229.08 lakh’ to ‘Rs. 324.08 lakh’; and which was further enhanced vide notification number S.O. 866(E) dated 27.4.2011 from ‘Rs.324.08 lakh’ to ‘Rs.454.08 lakh’;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.454.08 lakh” to “Rs.724.00 lakh”.

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from ‘Rs.454.08 lakh’ to ‘Rs.724.00 lakh’.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby i) notifies the scheme or project “Medical relief project”, which is being carried out by “Dardionu Rahat Fund, 102, Kashi Parekh Complex, 29, Adarsh Society, Navrangpura, Ahmedabad-380009”, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 and ii) amends the said notification number S.O. 399(E) dated 6.6.96 [read with notification numbers S.O. 510(E) dated 19.4.2004, S.O. 1601(E) dated 14.11.2005, S.O.1317(E) dated 4.6.2008 and S.O. 866(E) dated 27.4.2011], to the following effect, namely:-

‘In the said notification, in the Table against serial number (11), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.454.08 lakh”, the letters, figures and words “Rs.724.00 lakh” shall be substituted’.

[No. 9/2015 / F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 61(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28-9-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2349(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “गायत्री शहरी और ग्रामीण विकास सोसायटी, मकान नं. 11-168/2, ब्रह्मपुर, गुलबर्गा, कर्नाटक-585103” द्वारा “स्कूल छोड़ गए बच्चों के लिए सांय कक्षाएं, स्वयं-सहायता समूह बनाना, जूट की वस्तुएं और हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और 25 लाख रुपए की कार्पस निधि” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 25 लाख रुपए

की कार्पस निधि सहित 1.74 करोड़ रुपए अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा “गायत्री शहरी और ग्रामीण विकास सोसायटी, मकान नं. 11-168/2, ब्रह्मपुर, गुलबर्गा, कर्नाटक-585103” द्वारा चलाई जा रही “स्कूल छोड़ गए बच्चों के लिए सांय कक्षाएं, स्वयं-सहायता समूह बनाना, जूट की वस्तुएं और हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और 25 लाख रुपए की कार्पस निधि” की परियोजना अथवा स्कीम को 25 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 1.74 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगी।

[सं. 10/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 61(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2349(E) dated 28.9.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Evening classes for school dropout children, formation of self-help group, vocational training for making of Jute articles and handicraft articles, training programmes on production of wormy compost and corpus fund of Rs.25 lakh” by “Gayatri Urban and Rural Development Society, H.N.11-168/2, Brahmipur, Gulbarga, Karnataka -585103”, as

an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.74 crore including a corpus fund of Rs.25 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Evening classes for school dropout children, formation of self help group, vocational training for making of Jute articles and handicraft articles, training programmes on production of wormy compost and corpus fund of Rs.25 lakh.”, which is being carried out by “Gayatri Urban and rural Development society, H.N.11-168/2, Brahmipur, Gulbarga, Karnataka - 585103”, without any change in the approved cost of Rs.1.74 crore including a corpus fund of Rs.25 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption shall be available under Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 for the said financial year 2013-14.

[No. 10/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 62(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “बनजारा डवलपमेंट सोसायटी, फ्लैट सं. 102, साई किरण अपार्टमेंट (-1), श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500013, आंध्र प्रदेश” द्वारा “आंध्र प्रदेश के कुरनूल और प्रकाशम के नल्लामलाई वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजाति समूह चेंचु, अनुसूचित जनजातीय के स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार के लिए” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “बनजारा डबलेपमेंट सोसायटी, फ्लैट सं. 102, साई किरण अपार्टमेंट (-1), श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500013, आंध्र प्रदेश” द्वारा चलाई जा रही “आंध्र प्रदेश के कुरुनूल और प्रकाशम के नल्लामलाई वन क्षेत्रों में हरने वाले आदिम जनजाति समूह चेंचु, अनुसूचित जनजातीय के स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार के लिए” की परियोजना अथवा स्कीम को 1.74 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 11/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 62(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No.743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, “To improve Health status of the scheduled tribe, chenchu a primitive tribal group living in the Nallamallai forest areas of Kurnool and Prakasham districts of Andhra Pradesh” by “Banjara Development Society, Flat No 102, Sai Kiran Apartment-1, Srinagar Colony, Hyderabad -500073, Andhra Pradesh.”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.15 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax

Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “To improve Health status of the scheduled tribe, chenchu a primitive tribal group living in the Nallamallai forest areas of Kurnool and Prakasham districts of Andhra Pradesh”, which is being carried out by “Banjara Development Society, Flat No 102, Sai Kiran Apartment-1, Srinagar Colony, Hyderabad -500073, Andhra Pradesh.”, **without any change in the approved cost of Rs.1.15 crore**, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 11/2015 /F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 63(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8-8-1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 713(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री रामकृष्ण सेवाश्रम (स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र श्री शरदा देवी आंखों का अस्पताल), स्वामी विवेकानंद नगर, पावागढ़-561202, तुमकूर जिला, कर्नाटक” द्वारा “कुष्ठ रोग और क्षय रोग के उन्मूलन के लिए 30 बिस्तरे वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केंद्र के निर्माण, स्थापना और चलाने” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11-02-1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 99(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 12-12-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1217(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 23-3-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 386(अ) द्वारा तीन वित्तीय वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20-3-2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 496(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 12-3-2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 629(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना सं. का.आ. 496(अ), दिनांक 20-3-2007 द्वारा परियोजना लागत को ‘142 लाख रुपये’ से ‘292 लाख रुपये’ तक बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के “2.92 लाख से बढ़कर 8.00 लाख रुपये” होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 2.92 करोड़ रुपए से बढ़ाकर '8.00 करोड़ रुपए' करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 8-8-1995 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 713(अ), दिनांक 20-3-2007 अधिसूचना सं. का.आ. 496 (अ) के साथ पठित को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (2), कालम (4) के सामने सारणी में, “2.292 करोड़ रुपए” अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए “8.00 करोड़ रुपए” अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 12/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 63(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number SO.713(E) dated 08.08.1995 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, “Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural centre for elimination of leprosy and Tuberculosis” by “Sri Ramakrishna Sevashrama (Swami Vivekananda Integrated Rural Health Centre Shree Sharada Devi Eye Hospital), Swami Vivekananda Nagar, Pavagada-561202, Tumkur district, Karnataka.”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.15 crore for a period of three years ending with financial year 1998-99; which was further extended vide notification number S.O.99(E) dated 11.02.1999 for three years ending with financial year 2001-02; which was further extended vide notification number S.O.1217(E) dated 12.12.2001 for three years ending with financial year 2004-05; which was further extended vide notification number SO.No.386(E) dated 23.03.2005 for three years ending with financial year 2006-07; which was further extended vide notification number S.O.496(E) dated 20.03.2007 for three years ending with financial year 2009-

10; which was further extended vide notification number S.O. 1791(E) dated 21.7.2010 for three years ending with financial year 2012-13; and which was further extended vide notification number S.O. 629(E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas vide notification number S.O.496(E) dated 20.03.2007, the project cost was enhanced from ‘Rs. 142 lakh’ to ‘Rs. 292 lakh’;

And whereas the project cost is likely to enhance from “Rs.2.92 crore to Rs.8.00 crore”;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from “Rs.2.92 crore to Rs.8.00 crore”.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number SO.713(E) dated 08.08.1995 [read with notification number S.O.496(E) dated 20.03.2007], to the following effect, namely:-

‘In the said notification, in the Table against serial number (2), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.2.92 crore”, the letters, figures and words “Rs.8.00 crore” shall be substituted’.

[No. 12/2015 / F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 64(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18-5-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1250(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री वी आर देशपांडे ममोरियल ट्रस्ट(आर), उद्योग विद्यानगर, हलियल-581 329, कर्नाटक’ द्वारा “उत्तर कर्नाटक-एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (यूके-आईआरडीपी)” की परियोजना को 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 11-8-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1864(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “श्री वी आर देशपांडे ममोरियल ट्रस्ट(आर), उद्योग विद्यानगर, हलियल-581 329, कर्नाटक’ द्वारा “उत्तर कर्नाटक-एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (यूके-आईआरडीपी)” की परियोजना अथवा स्कीम को 4 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 13/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 64(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1250(E) dated 18.05.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, “Uttara Karnataka- Integrated Rural Development Project (UK-IRDP)” by “Shri V.R. Deshpande Memorial Trust(R), Udyog Vidyanagar, Haliyal - 581 329, Karnataka”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.4 crore for a period of two years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 1864(E) dated 11.8.2011 for three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 5 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Uttara Karnataka- Integrated Rural Development Project (UK-IRDP)”, which is being carried out by “Shri V.R.

Deshpande Memorial Trust(R), Udyog Vidyanagar, Haliyal- 581 329, Karnataka”, without any change in the approved cost of Rs.4 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 13/2015 /F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 65(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18-5-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1250(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सहारा हेल्थ एवं एज्युकेशनल सोसायटी, 39 डिफेंस पार्क, महेशताला, कोलकाता-700141’ द्वारा “गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) तथा आदिवासी परिवारों को आश्रय एवं मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने” की परियोजना को 8.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 9-10-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2399(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 9-10-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2399(अ) द्वारा परियोजना लागत को 8.45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11.75 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “सहारा हेल्थ एवं एज्युकेशनल सोसायटी, 39 डिफेंस पार्क, महेशताला, कोलकाता-700141’ द्वारा चलाई जा रही “गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) तथा आदिवासी परिवारों को आश्रय एवं मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने” की परियोजना अथवा स्कीम को 11.75 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष

2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 14/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 65(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1250 (E) dated 18.05.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Providing Shelter and Mobile Health Services to the BPL and Tribal Families” by “Sahara Health & Education Society, 39 Defence Park, Maheshtala, Kolkata - 700141”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.8.45 crore for a period of three years ending with financial year 2011-12; and which was further extended vide notification number S.O. 2399(E) dated 9.10.2012 for a period of three financial years ending with financial year 2014-15.

And whereas vide notification number S.O. 2399(E) dated 9.10.2012, the project cost was enhanced from Rs.8.45 crore to Rs.11.75 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Providing Shelter and Mobile Health Services to the BPL and Tribal Families”, which is being carried out by “Sahara Health & Education Society, 39 Defence Park, Maheshtala, Kolkata - 700141”, without any change in the approved cost of Rs.11.75 crore, for a further period of two years commencing with financial year 2015-16 and 2016-17.

[No. 14/2015 / F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 66(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12-1-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 121(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “पुरकाल युवा विकास सोसायटी, पुरकाल गांव, पोस्ट आफिस भगवंतपुर, देहरादून-248009, उत्तराखंड” द्वारा “बीटीटीपी (बस से उन्हें पुरकाल भेजना) की योजना, युवा शक्ति, युवा वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, स्त्री शक्ति” की परियोजना को 5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 14-6-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1377(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “पुरकाल युवा विकास सोसायटी, पुरकाल गांव, पोस्ट आफिस भगवंतपुर, देहरादून-248009, उत्तराखंड” द्वारा चलाई जा रही “बीटीटीपी (बस से उन्हें पुरकाल भेजना) की योजना, युवा शक्ति, युवा वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, स्त्री शक्ति” की परियोजना अथवा स्कीम को 5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 15/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 66(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) number S.O No.121(E) dated 12.01.2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Project for BTTP (Bus Them to Purkal) Scheme, Yuva Shakti, Young Adult Education Programme, Stree Shakti" by "The Purkal Youth Development Society, Purkal Village, P.O. Bhagwantpur, Dehradun 248 009, Uttarakhand", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.7 crore including a corpus fund of Rs. 5 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 1377(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Project for BTTP (Bus Them to Purkal). Scheme, Yuva Shakti, Young Adult Education Programme, Stree Shakti", which is being carried out by "The Purkal Youth Development Society, Purkal Village, P.O. Bhagwantpur, Dehradun 248 009, Uttarakhand", without any change in the approved cost of Rs. 7 crore including a corpus fund of Rs. 5 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 15/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 67(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल शिशु गृह, डीआईजेड एरिया, राजा बाजार, सेक्टर-4, गोल मार्किट के पास, नई दिल्ली-110001" द्वारा "(क) बच्चों में विकास हित, (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित दिल्ली में डेकेयर सेवाएं (ग) भारत की उत्तरी हिन्दी भाषी बेल्ट में प्रशिक्षण (घ) सभी छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह/चाइल्डकेयर व्यवस्था हेतु वकालत" की परियोजना को 8 करोड़ रुपये की कार्पस निधि के रूप में

अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 37 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 858(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि, अर्थात् 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल शिशु गृह, डीआईजेड एरिया, राजा बाजार, सेक्टर-4, गोल मार्किट के पास, नई दिल्ली-110001" द्वारा चलाई जा रही "(क) बच्चों में विकास हित, (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित दिल्ली में डेकेयर सेवाएं (ग) भारत की उत्तरी हिन्दी भाषी बेल्ट में प्रशिक्षण (घ) सभी छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह/चाइल्डकेयर व्यवस्था हेतु वकालत" की परियोजना अथवा स्कीम को 8 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 16/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 67(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 37, "a) Including Children in Development, b) Daycare services in Delhi including NCR region, c) Training in Northern Hindi speaking belt of India, d) Advocacy for crèche/childcare arrangements for all young children" by "Mobile Crèches for Working Mother's children, DIZ Area, Raja bazaar, Sector IV, Near Gole Market, New Delhi 110001", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.8

crore as corpus fund, for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 858(E) dated 27.4.2011 for a period of three years commencing with financial year 2011-12, i.e., 2011-12, 2012-13 and 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “a) Including Children in Development, b) Daycare services in Delhi including NCR region, c) Training in Northern Hindi speaking belt of India, d) Advocacy for crèche/childcare arrangements for all young children.”, which is being carried out by “Mobile Crèches for Working Mother’s children, DIZ Area, Raja bazaar, Sector IV, Near Gole Market, New Delhi 110001”, without any change in the approved cost of Rs. 8 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 16/2015/F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 68(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल शिशु गृह, डीआईजेड एरिया, राजा बाजार, सेक्टर-4, गोल मार्किट के पास, नई दिल्ली-110001” द्वारा “(क) बच्चों में विकास हित, (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित दिल्ली में डेकेयर सेवाएं (ग) भारत की उत्तरी हिन्दी भाषी बेल्ट में प्रशिक्षण (घ) सभी छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह/चाइल्डकेयर व्यवस्था हेतु वकालत” की परियोजना को 8 करोड़ रुपये की कार्पस निधि के रूप में अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 37 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 858(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि, अर्थात् 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा “कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए मोबाइल शिशु गृह, डीआईजेड एरिया, राजा बाजार, सेक्टर-4, गोल मार्किट के पास, नई दिल्ली-110001” द्वारा चलाई जा रही “(क) बच्चों में विकास हित, (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित दिल्ली में डेकेयर सेवाएं (ग) भारत की उत्तरी हिन्दी भाषी बेल्ट में प्रशिक्षण (घ) सभी छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह/चाइल्डकेयर व्यवस्था हेतु वकालत” की परियोजना अथवा स्कीम को, 8 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित के रूप में अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 17/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 68(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.06.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, “Advancement of Running and Support Education Institutions” by “Swami Vivekananda Education Trust, At:Nani Kadi Ta, Kadi, District Mehsana, Gujarat-382715”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.4.89 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14; and which was further extended vide notification number S.O.3848(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost is likely to enhance from “Rs.4.89 crore to Rs. 9.78 crore”;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from “Rs.4.89 crore to Rs. 9.78 crore”.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011, to the following effect, namely:-

‘In the said notification, in the Table against serial number (16), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs. 4.89 crore”, the letters, figures and words “Rs. 9.78 crore” shall be substituted’.

[No. 17/2015 / F.No.V. 27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 69(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13-3-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “एच.एम.एस. एज्युकेशन सोसायटी, शेड्टी हाली रोड, टुमकुर 572 102, कर्नाटक” द्वारा “विद्यमान 100 बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार (उपकरणों की खरीद, आवर्ती लागत तथा कार्पस निधि)” की परियोजना को 9 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 25.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 12 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 850(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “एच.एम.एस. एज्युकेशन सोसायटी, शेड्टी हाली रोड, टुमकुर 572 102, कर्नाटक” द्वारा चलाई जा रही “विद्यमान 100 बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार (उपकरणों की खरीद, आवर्ती लागत तथा कार्पस निधि)” की परियोजना अथवा स्कीम को 9 करोड़

रुपये की कार्पस निधि सहित 25.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 18/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 69(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737(E) dated 13.3.2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12, “Expansion of existing 100 bedded multi-speciality hospital (purchase of equipment, recurring cost and corpus fund)” by “H.M.S Education Society, Shetty Halli Road, Tumkur 572 102, Karnataka”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 25.05 crore including a corpus fund of Rs.9 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 850(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Expansion of existing 100 bedded multi-speciality hospital (purchase of equipment, recurring cost and corpus fund)”, which is being carried out by “H.M.S Education Society, Shetty Halli Road, Tumkur 572 102, Karnataka”, without any change in the approved cost of Rs. 25.05 crore including a corpus fund of Rs.9 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 18/2015 / F. No. V. 27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 70(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16-7-2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1145(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “हेल्थ फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर रालीयाटी, दाहोड, गुजरात 389151” द्वारा “अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तथा मुफ्त वार्ड सहित मुफ्त सुविधाओं के उन्नयन एवं प्रावधान” की परियोजना को 7.87 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 25.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 21-7-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “हेल्थ फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर रालीयाटी, दाहोड, गुजरात 389151” द्वारा “अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तथा मुफ्त वार्ड सहित मुफ्त सुविधाओं के उन्नयन एवं प्रावधान” की परियोजना अथवा स्कीम को, 7.87 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 25.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 क ग के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगी।

[सं. 19/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 70(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1145(E) dated 16.07.2007 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1 “Up-gradation and Provision of Additional Health Care Facility and Free Ward plus free facility” by “Health Foundation & Research Centre Raliyati, Dahod, Gujarat – 389151”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 25.05 crore including a corpus fund of Rs.7.87 crore, for a period of three years ending with financial year 2009-10; and which was further extended vide notification number 1790(E) dated 21.7.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Up-gradation and Provision of Additional Health Care Facility and Free Ward plus free facility”, which is being carried out by “Health Foundation & Research Centre, Raliyati, Dahod, Gujarat – 389151”, **without any change in the approved cost of Rs.7.87 crore**, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, 2014-15 and 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, exemption under Section 35AC of IT Act shall not be available for the said financial year 2013-14.

[No. 19/2015/F.No. V. 27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 71(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3-10-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सरदार पटेल हेल्थ फाउंडेशन, सचिद्वानंद प्लॉट सं. 2701, पटेल पार्क के पीछे, एयरोड्रोम रोड, भावनगर-364001, गुजरात” द्वारा “वर्तमान क्रियाकलापों के विस्तार और सहायता अर्थात्

आवृत्ति घाटों को पूरा करने और अस्पताल के भावी घाटे के लिए कार्पस निधि सृजित करने” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 530.25 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 750.51 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 14 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “सरदार पटेल हेल्थ फाउंडेशन, सच्चिदानंद प्लॉट सं. 2701, पटेल पार्क के पीछे, एयरोड्रोम रोड, भावनगर-364001, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “वर्तमान क्रियाकलापों के विस्तार और सहायता अर्थात् आवृत्ति घाटों को पूरा करने और अस्पताल के भावी घाटे के लिए कार्पस निधि सृजित करने” की परियोजना अथवा स्कीम को, 530.25 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 750.51 लाख रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 20/2015/फा. सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 71(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, “For extension & support of present activities i.e., to meet with recurring deficits and to create corpus fund for future deficit of the hospital” by “Sardar Patel Health Foundation, Sachchidanand Plot No.2701, Behind Patel Park, Aerodrome Road, Bhavnagar-364001, Gujarat”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.750.51 lakh including corpus fund of Rs.530.25 lakh,

for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “For extension & support of present activities i.e., to meet with recurring deficits and to create corpus fund for future deficit of the hospital”, which is being carried out by “Sardar Patel Health Foundation, Sachchidanand Plot No.2701, Behind Patel Park, Aerodrome Road, Bhavnagar-364001, Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.750.51 lakh including corpus fund of Rs.530.25 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 20/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 72(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री लोक सेवक संघ, लोक विद्या मंदिर, गांव थोराडी, जिला अमरेली-364522, गुजरात” द्वारा “विस्तार और सहायक क्रियाकलापों” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 311 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 465.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “श्री लोक सेवक संघ, लोक विद्या मंदिर, गांव थोराडी, जिला अमरेली-364522, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “विस्तार और सहायक क्रियाकलापों” की परियोजना अथवा स्कीम को, 311 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 465.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 21/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 72(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, “Extension & support activities” by “Shri Lok Sevak Sangh, Lok Vidya Mandir, Village Thoradi, District Amreli – 364522, Gujarat”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.465.00 lakh including corpus fund of Rs. 311 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Extension & support activities”, which is being carried out by “Shri Lok Sevak Sangh, Lok Vidya Mandir, Village Thoradi, District Amreli – 364522. Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.465.00 lakh including corpus fund of Rs.311 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 21/2015 /F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 73(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1462(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “मंगल जीवन ट्रस्ट, सेडराना, डाकघर-सेडराना, जिला पाटन (उत्तरी गुजरात), पोस्ट बॉक्स नं. 16, अहमदाबाद-227527” द्वारा “वृद्ध व्यक्तियों और बेसहारा बच्चों के लिए घर प्रदान करने” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 2.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 11-8-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1882(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “मंगल जीवन ट्रस्ट, सेडराना, डाकघर-सेडराना, जिला पाटन (उत्तरी गुजरात), पोस्ट बॉक्स नं. 16, अहमदाबाद-227527” द्वारा चलाई जा रही “वृद्ध व्यक्तियों और बेसहारा बच्चों के लिए घर प्रदान करने” की परियोजना अथवा स्कीम को 40 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 2.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 22/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 73(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) number S.O 1462(E) dated 17.06.2008 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Providing home for old aged persons and lonely children" by "Mangal Jeevan Trust, At & PO: Sedrana, District Patan (North Gujarat), Post Box No.16, Ahmedabad-227527.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.70 crore including a corpus fund of Rs. 40 lakh, for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 1882(E) dated 11.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Providing home for old aged persons and lonely children", which is being carried out by "Mangal Jeevan Trust, At & PO: Sedrana, District Patan(North Gujarat), Post Box No.16, Ahmedabad-227527.", without any change in the approved cost of Rs. 2.70 crore including a corpus fund of Rs. 40 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 22/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 74(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12-1-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 121(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया वसंत विहार, दरवाजा सं. 124-126 (पुराना नं. 64-65), ग्रीनवेज रोड, राजा अन्नामलईपुरम, चेन्नई-600028, तमिलनाडु" द्वारा "ऋषि वैल्ली ग्रामीण शिक्षा केंद्र" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 881(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया वसंत विहार, दरवाजा सं. 124-126 (पुराना नं. 64-65), ग्रीनवेज रोड, राजा अन्नामलईपुरम, चेन्नई-600028, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "ऋषि वैल्ली ग्रामीण शिक्षा केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.5 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 23/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 74(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.121(E) dated 12.01.2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Rishi Valley Rural Education Centre" by "Krishnamurthi Foundation India, Vasant Vihar, Door No. 124-126 (old No.64-65), Greenways Road, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028, Tamilnadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.5 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 881(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Rishi Valley Rural Education Centre”, which is being carried out by “Krishnamurthi Foundation India, Vasant Vihar, Door No. 124-126 (old No.64-65), Greenways Road, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028, Tamilnadu”, without any change in the approved cost of Rs.1.5 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 23/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 75(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23-2-2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 154(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री दक्षिणया भाव समिति डी.सं. 4-2-16, चौथी लाइन, लक्ष्मीपुरम, गुंटूर-522007, आंध्र प्रदेश” द्वारा “पडापलकालुरू गांव में विशेष विद्यालय छात्रावास के लिए भवन और स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 267.80 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 9-12-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1278(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2004-05 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 4-4-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 497(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1476(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसें बाद में दिनांक 12-03-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 660(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 12-3-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 660(अ) के तहत परियोजना लागत को ‘267.80 लाख रुपये से बढ़ाकर ‘459.80 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पंद्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त

परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “श्री दक्षिणया भाव समिति डी.सं. 4-2-16, चौथी लाइन, लक्ष्मीपुरम, गुंटूर-522007, आंध्र प्रदेश” द्वारा चलाई जा रही “पडापलकालुरू गांव में विशेष विद्यालय छात्रावास के लिए भवन और स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण” की परियोजना अथवा स्कीम को 459.80 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 24/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 75(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O 154(E) dated 23.2.2000 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, “Construction of building for special school hostel and staff quarters, purchase of equipment, furnishing and running of Dakshinya Institute for the mentally handicapped at Padapalkaluru village, Guntur” by “Sri Dakshinya Bhava Samithi, D.No.4-2-16, 4th Line, Lakshmipuram, Guntur-522007, Andhra Pradesh”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 267.80 lakh, for a period of three years ending with financial year 2002-03; which was further extended vide notification number S.O. 1278(E) dated 9.12.2002 for three years ending with financial year 2004-05; which was extended further vide notification number S.O.497(E) dated 04.04.2006 for three more years ending with financial year 2007-08; which was further extended vide notification number S.O. No. 1476 (E) dated 17.06.2008 for three years ending with financial Year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 660(E) dated 12.3.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas vide notification number S.O. 660(E) dated 12.3.2011, the project cost was enhanced from ‘Rs. 267.80 lakh’ to ‘Rs. 459.80 lakh’;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 15 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Construction of building for special school hostel and staff quarters, purchase of equipment, furnishing and running of Dakshinya Institute for the mentally handicapped at Padapalkaluru village, Guntur”, which is being carried out by “Sri Dakshinya Bhava Samithi, D.No.4-2-16, 4th Line, Lakshmiapuram, Guntur -522007, Andhra Pradesh”, without any change in the approved cost of Rs.459.80 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 24/2015 / F.No.V.27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 76(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14-6-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “विक्लांगों की राहत और पुनर्वास के लिए श्रीमती पारसनबेन नारनदास रामजी शाह (तलजावाला) सोसायटी, प्लॉट सं. 51, विद्यानगर सर्किल के पास, भावनगर-364002” द्वारा “प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए क्रियाकलापों का विस्तार और सहायता” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 363 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 590 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 25 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के

साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “विक्लांगों की राहत और पुनर्वास के लिए श्रीमती पारसनबेन नारनदास रामजी शाह (तलजावाला) सोसायटी, प्लॉट सं. 51, विद्यानगर सर्किल के पास, भावनगर-364002” द्वारा चलाई जा रही “प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए क्रियाकलापों का विस्तार और सहायता” की परियोजना अथवा स्कीम को 363 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 590 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 25/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 76(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 25 “Extension and Support of Activities for Cerebral Palsy Children” by “Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah (Talajawala) Society for Relief & Rehabilitation of the Disabled, Plot No. 51, Near Vidyanagar Circle, Bhavnagar 364 002”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.590 lakh including a corpus fund of Rs.363 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Extension and Support of Activities for Cerebral Palsy Children”, which is being carried out by “Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah (Talajawala) Society for Relief & Rehabilitation of the Disabled, Plot No. 51, Near Vidyanagar Circle, Bhavnagar 364 002”, without any change in the approved cost of Rs.590 lakh including a corpus fund of

Rs.363 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 25/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 77(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “विद्यानिकेतन सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुउद्देश्यीय सेवाभावी संस्था धामदोड, डाकघर उमर्दे खुर्द, नंदुरबार, महाराष्ट्र-425411” द्वारा “आवासयी नेत्रहीन विद्यालय के विस्तार” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14-6-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1376(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 ककग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “विद्यानिकेतन सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुउद्देश्यीय सेवाभावी संस्था धामदोड, डाकघर उमर्दे खुर्द, नंदुरबार, महाराष्ट्र-425411” द्वारा चलाई जा रही “आवासीय नेत्रहीन विद्यालय के विस्तार” की परियोजना अथवा स्कीम को 3.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 26/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 77(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7 “Expansion of residential Blind School” by “Vidyaniketan Sanskritik, Samajik, Shikshanik, Bahuuddeshiya Sevabhavi Sanstha, Dhamdod, Post Umarde Khurde, Nandurbar, Maharashtra- 425 411”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.3.61 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11; and which was further extended vide notification number S.O. 1376(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Expansion of residential Blind School”, which is being carried out by “Vidyaniketan Sanskritik, Samajik, Shikshanik, Bahuuddeshiya Sevabhavi Sanstha, Dhamdod, Post Umarde Khurde, Nandurbar, Maharashtra- 425 411”, without any change in the approved cost of Rs.3.61 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 26/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 78(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22-01-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “बंसाली ट्रस्ट, 640-646, पंचरतन मामा परमानंद मार्ग, मुम्बई-400004” द्वारा “एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना” को 12.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना

अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 4-9-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1413(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 17-06-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1479(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 853(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1479(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 12.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 18.94 करोड़ रुपये कर दिया गया था; और दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 853(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 18.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 32.14 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 32.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 45.24 करोड़ रुपये होने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को '32.14 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45.24 करोड़ रुपये' करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "बंसाली ट्रस्ट, 640-646, पंचरतन मामा परमानंद मार्ग, मुम्बई-400004" द्वारा चलाई जा रही "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) दिनांक 22-1-2003 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 6 के कॉलम (4) में, जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '32.14 करोड़ रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर

'45.24 करोड़ रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 27/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 78(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.60(E) dated the 22nd January, 2003, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Integrated Rural Development Project" by "Bhansali Trust, 640-646, Panchratna Mama Parmanand Marg, Mumbai-400004", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 12.75 crore, for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.1413(E) dated the 4th September, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O.1479(E) dated 17th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 853(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas by notification number S.O. 1479(E) dated 17th June, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs. 12.75 crore to 18.94 crore; and vide notification number S.O. 853(E) dated 27.4.2011 the estimated cost was further enhanced from Rs.18.94 crore to Rs.32.14 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 32.14 crore to Rs. 45.24 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from 'Rs. 32.14 crore to Rs. 45.24 crore'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); (a) hereby notifies the scheme or project "Integrated Rural Development Project", which is being carried out by "Bhansali Trust, 640-646, Panchratna Mama Parmanand Marg, Mumbai-400004" for a period of three more years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) Further amends the said notification number S.O.60(E) dated the 22nd January, 2003, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word “Rs. 32.14 crore” the letters, figures and word “Rs. 45.24 crore” shall be substituted.

[No. 27/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 79(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11-8-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1860(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “महागुजरात मेडीकल सोसायटी, कालेज रोड नाडियाड, जिला खेड़ा, गुजरात” द्वारा “कैंसर विभाग के उन्नयन तथा उपकरणों व मशीनरी की खरीद” की परियोजना को, 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 31.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “महागुजरात मेडीकल सोसायटी, कालेज रोड नाडियाड, जिला खेड़ा, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “कैंसर विभाग के उन्नयन तथा उपकरणों व मशीनरी की खरीद” की परियोजना अथवा स्कीम को, 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 31.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 28/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 79(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1860(E) dated 11.8.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number ‘4’ “For upgrading and purchasing equipments and machineries for cancer department.” by “Mahagujarat Medical Society, College Road Nadiad, District Kheda, Gujarat.”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.31.45 crore including corpus fund of Rs. 2.00 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “For upgrading and purchasing equipments and machineries for cancer department.”, which is being carried out by “Mahagujarat Medical Society, College Road Nadiad, District Kheda, Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.31.45 crore including corpus fund of Rs. 2.00 crore, for a further period of two years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15 and 2015-16.

[No. 28/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 80(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3-10-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “एकता शक्ति फाउंडेशन, ए-112, द्वितीय तल, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018” द्वारा “मध्याह्न भोजन अर्ध-स्वचालित रसोईघर और रसोईघर के उन्नयन” की परियोजना को, 11.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “एकता शक्ति फाउंडेशन, ए-112, द्वितीय तल, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018” द्वारा चलाई जा रही “मध्याह्न भोजन अर्धस्वचालित रसोईघर और रसोईघर के उन्नयन” की परियोजना अथवा स्कीम को, 11.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 29/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 80(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number ‘11’ ‘Mid day meal semi automated kitchen and upgrading of kitchens’ by “Ekta Shakti Foundation, A-112, IInd Floor, Vikaspuri, New Delhi 110018”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.11.68 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project ‘Mid day meal semi automated kitchen and upgrading of kitchens’ which is being carried out “Ekta Shakti

Foundation A-112, IInd Floor, Vikaspuri, New Delhi 110018”, without any change in the approved cost of Rs.11.68 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 29/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 81(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10-09-1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 739(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “भगवान महावीर विक्लांग सहायता समिति, सवाय मानसिंह अस्पताल कैम्पस, जयपुर-302004, राजस्थान” द्वारा “जयपुर, राजस्थान में ऐम्प्यूटी, पोलियो से प्रभावित विक्लांग व्यक्तियों, ऊँचा सुनने वालों को कृत्रिम अंग व पुनर्वास हेतु अन्य यंत्र, दवाईयाँ तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष जूते, विक्लांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार व पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराने” की परियोजना को, 350.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से, निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 22-1-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 66(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 14-11-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1609(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 21-1-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 250(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 14-6-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1398(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 14-11-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1609(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 350.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 650.00 लाख रुपये कर दिया गया था; और दिनांक 21-01-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 250(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 06.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था; और दिनांक 14-6-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1398(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 11.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पंद्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के '23.00 करोड़ रुपये' से बढ़कर '35.45 करोड़ रुपये' होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को '23.00 करोड़ रुपये' से बढ़ाकर '35.45 करोड़ रुपये' करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल कैम्पस, जयपुर-302004, राजस्थान" द्वारा चलाई जा रही "जयपुर, राजस्थान में ऐम्प्यूटी, पोलियो से प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, ऊँचा सुनने वालों को कृत्रिम अंग व पुनर्वास हेतु अन्य यंत्र, दवाईयाँ तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष जूते, विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार व पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 739(अ) दिनांक 10-09-1999 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 7 के कॉलम (4) में, जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '23.00 करोड़ रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '35.45 करोड़ रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 30/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 81(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.739(E) dated the 10th September, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Provision of artificial limbs

and other rehabilitation aids to amputees, polio-affected disabled persons, hard of hearing, medicines and special shoes to persons suffering from leprosy, various types of financial aids and other support for self-employment and rehabilitation of handicapped persons at Jaipur, Rajasthan" by "Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Sawai Man Singh Hospital Camps, Jaipur-302004, Rajasthan", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 350.00 lakh, for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.66(E) dated the 22nd January, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S.O.1609(E) dated the 14th November, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O.250(E) dated 21st January, 2009 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number 1398(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.1609(E) dated the 14th November, 2005 the estimated cost was enhanced from Rs. 350.00 lakh to Rs.650.00 lakh and vide notification number S.O.250(E) dated the 21st January, 2009 the estimated cost was enhanced from Rs. 6.50 crore to 11.50 crore; vide notification number 1398(E) dated 14.6.2011 the estimated cost was enhanced from Rs.11.50 crore to Rs.23.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.23.00 crore' to 'Rs.35.45 crore;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also amending the project cost from 'Rs.23.00 crore' to 'Rs.35.45 crore.'

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); (a) hereby notifies the scheme or project "Provision of artificial limbs and other rehabilitation aids to amputees, polio-affected disabled persons, hard of hearing, medicines and special shoes to persons suffering from leprosy, various types of financial aids and other support for self-employment and rehabilitation of handicapped persons at Jaipur, Rajasthan", being carried out by "Bhagwan Manaveer Viklang Sahayata Samiti, Sawai Man Singh Hospital Camps, Jaipur-302004, Rajasthan" for a further period of three years commencing

with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 739(E) dated the 10th September, 1999, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 7, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under Section 35AC, for the letters, figures and word “Rs.23.00 crore” the letters, figures and word “Rs.35.45 crore” shall be substituted.

[No. 30/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 82(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11-5-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “भारतीय शैक्षिक संस्थान, बी.एम. 135, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश” द्वारा “अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा ग्रामीण गरीब (गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), महिलाओं हेतु आय सृजन के कार्यक्रम, स्कूल छोड़ने वाले ग्रामीण बच्चों एवं नव साक्षर महिलाओं के लिए साक्षरता के प्रति जागरूकता” की परियोजना को, 1.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35 क ग के तहत छूट उपलब्ध नहीं दी जाएगी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “भारतीय शैक्षिक संस्थान, बी.एम. 135, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश” द्वारा चलाई जा रही “अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा ग्रामीण गरीब (गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), महिलाओं हेतु आय सृजन के कार्यक्रम, स्कूल छोड़ने वाले ग्रामीण बच्चों एवं नव साक्षर महिलाओं के लिए साक्षरता के प्रति जागरूकता”

की परियोजना को, 1.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 31/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 82(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1052(E) dated 11.5.2010 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number ‘3’ ‘Income Generate programme for SC, ST & rural poor (BPL), women’s and literacy awareness for rural drop out children’s and neo literate women’ by “Bhartiya Shaikshik Sansthan, B.M. 135, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.96 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption under Section 35AC shall be available for the said financial year 2013-14.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Income Generate programme for SC, ST & rural poor (BPL), women’s and literacy awareness for rural drop out children’s and neo literate women”, which is being carried out “Bhartiya Shaikshik Sansthan, B.M. 135, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh” without any change in the approved cost of Rs.1.96 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16.

[No. 31/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 83(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6-6-1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 339(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “पोलियो फाउंडेशन, विक्लांगों के लिए शाह चीमनलाल छोटालाल लोखंडवाला चेरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, रायपुर, चेकला, अहमदाबाद-1” द्वारा “अहमदाबाद, गुजरात में पोलियो अस्पताल हेतु उपकरण एवं संचालन” की परियोजना को, 63.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से, निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 11-05-1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 07-6-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 3-2-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 153(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 4-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1306(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 27-4-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 861(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 11-5-1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 63.15 लाख रुपये से बढ़ाकर 71.50 लाख रुपये कर दिया गया था; और दिनांक 3-2-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 153(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 71.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 151.35 लाख रुपये कर दिया गया था; दिनांक 25-3-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 845(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 151.35 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था; और दिनांक 30-12-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3067(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 3.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.55 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के ‘7.55 करोड़ रुपये’ से बढ़कर ‘13.55 करोड़ रुपये’ होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त

परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को ‘7.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ‘13.55 करोड़ रुपये’ करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “पोलियो फाउंडेशन, विक्लांगों के लिए शाह चीमनलाल छोटालाल लोखंडवाला चेरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, रायपुर, चेकला, अहमदाबाद-1” द्वारा चलाई जा रही “अहमदाबाद, गुजरात में पोलियो अस्पताल हेतु उपकरण एवं संचालन” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ) दिनांक 6-6-1996 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 8 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में ‘7.55 करोड़ रुपये’ अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर ‘13.55 करोड़ रुपये’ अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 32/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 83(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.399(E) dated the 6th June, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “Equipments and running of Polio Hospital at Ahmedabad, Gujarat” by “Polio Foundation, Shah Chimenlal Chhotalal Lokandwala Charitable Trust Hospital for the Handicapped, Raipur, Chekla, Ahmedabad-1”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 63.15 lakh for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.324(E) dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.614(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further

vide notification number S.O.153(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.1306(E) dated the 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-2009; and which was further extended vide notification number S.O. 861 (E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.324(E) dated the 11th May, 1999 the estimated cost was enhanced from Rs. 63.15 lakh to Rs.71.50 lakh; vide notification number S.O.153(E) dated the 3rd February, 2006 the estimated cost was further enhanced from Rs.71.50 lakh to Rs.151.35 lakh; vide notification number S.O.845(E) dated 25th March, 2009 the estimated cost was further enhanced from 151.35 lakh to Rs. 3 crore; and vide notification number S.O. 3067(E) dated 30th December, 2010 the estimated cost was further enhanced from 3.00 crore to 7.55 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the project cost is likely to enhance from 'Rs.7.55 crore' to 'Rs.13.55 crore';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from 'Rs.7.55 crore' to 'Rs.13.55 crore'.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project "Equipments and running of Polio Hospital at Ahmedabad, Gujarat", which is being carried out by "Polio Foundation, Shah Chimenlal Chhotalal Lokandwala Charitable Trust Hospital for the Handicapped, Raipur, Chekla, Ahmedabad - 1", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) Further amends the said notification number S.O.399 (E) dated the 6th June, 1996, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and word "Rs.7.55 crore" the letters, figures and word "Rs.13.55 crore" shall be substituted.

[No. 32/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 84(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14-6-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "वीसामो किड्स फाउंडेशन", इनडक्टोथर्म के सामने, भोपाल, अहमदाबाद-380058" द्वारा "वीसामो किड्स फाउंडेशन" की परियोजना को, 38.58 लाख रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 38.58 लाख रुपये से बढ़कर 1.97 लाख रुपये होने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को '38.58 लाख रुपये' से बढ़ाकर 1.97 लाख रुपये ' करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "वीसामो किड्स फाउंडेशन", इनडक्टोथर्म के सामने, भोपाल, अहमदाबाद-380058" द्वारा चलाई जा रही "वीसामो किड्स फाउंडेशन" की परियोजना का वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) दिनांक 14-6-2011 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 21 के कॉलम (4) में, धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '38.58 लाख रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '1.97 लाख रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 33/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 84(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 21, “Visamo Kids Foundation” by “Visamo Kids Foundation, Opposite Inductotherm, Bopal, Ahmedabad -380058”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.38.58 lakh, for a period of two years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 2 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from ‘Rs.38.58 lakh’ to ‘Rs.1.97 crore’;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from ‘Rs.38.58 lakh’ to ‘Rs.1.97 crore’.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (a) notifies the scheme or project “Visamo Kids Foundation”, which is being carried out by “Visamo Kids Foundation, Opposite Inductotherm, Bopal, Ahmedabad -380058” for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption under Section 35AC shall be available for the said financial year 2013-14.

(b) further amends the said notification number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 to the following effect namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 21, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters figures and word ‘Rs.38.58 lakh’, the letters figures and word ‘Rs.1.97 crore’ shall be substituted.

[No. 33/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 85(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30-3-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 458 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “विद्या प्रतिष्ठान, विद्यानगरी, भिगवान रोड, बारामती, पुणे-413133, महाराष्ट्र” द्वारा “जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलोजी) के माध्यम से सतत विकास” की परियोजना को, 13.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2371 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 873 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “विद्या प्रतिष्ठान, विद्यानगरी, भिगवान रोड, बारामती, पुणे-413133, महाराष्ट्र” द्वारा चलाई जा रही “जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलोजी) के माध्यम से सतत विकास” की परियोजना को 13.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 34/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 85(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.458(E) dated the 30th March, 2006, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, “Sustainable development through biotechnology” by “Vidya Pratishthan, Vidyanagari, Bhigwan Road, Baramati, Pune - 413133, Maharashtra”, as an eligible project or scheme, at estimated cost of Rs.13.94 crore for a period of three years beginning with

financial year 2005-2006; which was extended vide notification number S.O. 2371(E) dated 3rd October, 2008 for further period of three years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended for further three years vide notification number S.O. 873(E) dated 27th April, 2011, ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sustainable development through biotechnology" which is being carried out by "Vidya Pratishthan, Vidyanagari, Bhigwan Road, Baramati, Pune - 413133, Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs.13.94 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 34/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 86(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 08-08-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1111(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "अक्षर ट्रस्ट, मेघदूत, आर.सी. दत्त रोड, अल्कापुरी, बड़ोदा-390007" द्वारा "ऊँचा सुनने वालों के लिए अक्षर केन्द्र" की परियोजना को, 62.61 लाख रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 17-06-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1463(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 27-04-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 871(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 62.61 लाख रुपये से बढ़कर 132 लाख रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को '62.61 लाख रुपये से बढ़ाकर 132 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "अक्षर ट्रस्ट, मेघदूत, आर.सी. दत्त रोड, अल्कापुरी, बड़ोदा-390007" द्वारा चलाई जा रही "ऊँचा सुनने वालों के लिए अक्षर केन्द्र" को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1111(अ) दिनांक 08-08-2005 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 7 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '62.61 लाख रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '132 लाख रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 35/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 86(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1111(E) dated the 8th August, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Akshar centre for hearing impaired" by "Akshar Trust, Meghdoot, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda-390007", as an eligible project or scheme, at estimated cost of Rs. 62.61 lakh for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended vide notification number S.O. 1463(E) dated 17th June, 2008 for further period of three years beginning with

financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 871(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.62.61 lakh to Rs. 132 lakh';

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from 'Rs.62.61 lakh to Rs. 132 lakh' ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (a) notifies the scheme or project "Akshar centre for hearing impaired" which is being carried out by Akshar centre for hearing impaired" by "Akshar Trust, Meghdoot, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda-390007", for a period of three more years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 1111(E) dated the 8th August, 2005 to the following effect namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 7, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters figures and word "Rs.62.61 lakh", the letters figures and word "Rs. 132 lakh" shall be substituted.

[No. 35/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 87(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 03-02-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 135(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, एम.सी.डी. शॉपिंग काम्प्लेक्स, प्रथम तल (केन्द्रीय विद्यालय के पास), टैगोर एक्सटेंशन, पी.ओ. बॉक्स सं. 6557, नई दिल्ली-110027" द्वारा "किशोरों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र" की परियोजना को, 2.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में

क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था; जिसे दिनांक 04-06-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1311(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 16-06-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1372(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 2.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है ।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को '2.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, एम.सी.डी. शॉपिंग काम्प्लेक्स, प्रथम तल (केन्द्रीय विद्यालय के पास), टैगोर एक्सटेंशन, पी.ओ. बॉक्स सं. 6557, नई दिल्ली-110027" द्वारा चलाई जा रही "किशोरों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 135(अ) दिनांक 03-02-2006 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 7 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '2.00 करोड़ रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '3.00 करोड़ रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 36/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 87(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) number S.O.135(E) dated the 3rd February, 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, “National Centre for Adolescents” by “Urivi Vikram Charitable Trust, MCD Shopping Complex, 1st Floor (Near Central School), Tagore Garden Extension, P.O. Box No.6557, New Delhi – 110027”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.00 crore for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O. 1311(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O. 1372(E) dated 16.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.2.00 crore to ‘Rs. 3.00 crore’;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from ‘Rs. 2.00 crore to Rs. 3.00 crore’;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (a) notifies the scheme or project “National Centre for Adolescents” being carried out by “Urivi Vikram Charitable Trust, MCD Shopping Complex, 1st Floor (Near Central School), Tagore Garden Extension, P.O. Box No.6557, New Delhi – 110027”, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O. 135(E) dated the 3rd February, 2006 to the following effect namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 7, in column (4) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters figures and word “Rs. 2.00 crore, the letters figures and word “Rs. 3.00 crore’ shall be substituted.

[No. 36/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 88(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री बिडाडा सर्वोदय ट्रस्ट, शाह कल्याणजी मावजी पटेल आरोग्यधाम, गांव बिडाडा, ताल मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात-370435” द्वारा “श्री बिडाडा सर्वोदय ट्रस्ट, शाह कल्याणजी मावजी पटेल आरोग्यधाम” की परियोजना को, 10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि के रूप में अनुमानित लागत से, वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “श्री बिडाडा सर्वोदय ट्रस्ट, शाह कल्याणजी मावजी पटेल आरोग्यधाम, गांव बिडाडा, ताल मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात-370435” द्वारा चलाई जा रही “श्री बिडाडा सर्वोदय ट्रस्ट, शाह कल्याणजी मावजी पटेल आरोग्यधाम” की परियोजना को, 10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि के रूप में अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 37/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 88(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 743(E) dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the

Central Government had notified at serial number '15' 'Shree Bidada Sarvodaya Trust Shah Kalyanji Mavji Patel Arogyadham' by "Shree Bidada Sarvodaya Trust, Shah Kalyanji Mavji Patel Arogyadham, Village Bidada, Tal Mandvi, District Kutch, Gujarat 370435", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.10 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project 'Shree Bidada Sarvodaya Trust Shah Kalyanji Mavji Patel Arogyadham' which is being carried out "Shree Bidada Sarvodaya Trust, Shah Kalyanji Mavji Patel Arogyadham, Village Bidada, Tal Mandvi, District Kutch, Gujarat 370435", without any change in the approved cost of Rs.10 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 37/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 89(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19-12-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री शनिश्चर देवस्थान ट्रस्ट डाकघर शनी सिंगानापुर, ताल्लुका-नेवासा, जिला अहमदनगर" द्वारा "श्री शनिश्चर ग्रामीण रुग्णालय की सुविधाओं का विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 8.67 करोड़ रुपए अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,

इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "श्री शनिश्चर देवस्थान ट्रस्ट डाकघर शनी सिंगानापुर, ताल्लुका-नेवासा, जिला अहमदनगर" द्वारा चलाई जा रही "श्री शनिश्चर ग्रामीण रुग्णालय की सुविधाओं का विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को 8.67 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 38/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 89(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number '20' 'Expansion facilities of Shri Shanishwar Gramin Rugnalay' by "Shri Shanishwar Devasthan Trust At/Post- Shani Shinganapur, Tal-Newasa Dist-Ahemadnagar", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.8.67 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project 'Expansion facilities of Shri Shanishwar Gramin Rugnalay' which is being carried out "Shri Shanishwar Devasthan Trust At/Post- Shani Shinganapur, Tal-Newasa Dist-Ahemadnagar", without any change in the approved cost of Rs.8.67 crore, for a further period of three years

commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 38/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 90(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30-03-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 458(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “विद्या प्रतिष्ठान, विद्यानगरी, भीगवान रोड, बारामाती जिला, पुणे-413133, महाराष्ट्र” द्वारा “निर्धनों का सशक्तिकरण-ग्रामीण विकास” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 28.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2390(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27-4-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 874(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “विद्या प्रतिष्ठान, विद्यानगरी, भीगवान रोड, बारामाती जिला, पुणे-413133, महाराष्ट्र” द्वारा चलाई जा रही “निर्धनों का सशक्तिकरण-ग्रामीण विकास” की परियोजना अथवा स्कीम को 28.21 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 39/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 90(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.458(E) dated the 30th March, 2006, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, “Empowering the poor-rural development project” by “Vidya Pratishthan, Vidyanagari, Bhigwan Road, Baramati District, Pune – 413133, Maharashtra”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 28.21 crore for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended vide notification number S.O. 2390(E) dated 3rd October, 2008 for further period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended for three years vide notification number 874(E) dated 27th April, 2011, ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Empowering the poor-rural development project” which is being carried out by “Vidya Pratishthan, Vidyanagari, Bhigwan Road, Baramati District, Pune – 413133, Maharashtra”, without any change in the approved cost of Rs.28.21 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 39/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 91(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12-12-1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 862(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नारायण सेवा संस्थान ‘सेवा धाम’, 483, हिरण मागरी, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान-313002” द्वारा “हिरण मागरी,

सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र का संचालन” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1998-1999 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 26-5-2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 508(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 5-7-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 785(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 5-7-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1013(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 480(अ) वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27-12-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2895(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 785(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 2.91 करोड़ रुपये से 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया था; दिनांक 15 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 249(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपये से 2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 34,23,86,748.00 रुपये तक और बढ़ाया गया था और दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 840(अ) द्वारा अनुमोदित लागत को 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 34.23 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 64.24 करोड़ रुपये तक और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपये से बढ़कर ‘2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपये’ होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को ‘2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपये से बढ़कर ‘2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 12 दिसंबर, 1997 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 862(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम सं. (2) कालम (4) के सामने सारणी में, “2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 64.28 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए “2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 104.40 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 40/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मन्मथ लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 91(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.862(E) dated the 12th December, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, “Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research Centre at Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan” by “Narayan Seva Sanstha, “Seva Dham”, 483, Hiran Magri, Sector-4, Udaipur, Rajasthan – 313002”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999; which was extended further vide notification number S.O.508(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002; which was extended further vide notification number S.O.785(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.1013(E) dated the 5th July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 840(E) dated 25th March, 2009 for a period of three year beginning with financial year 2009-10; and which was further extended vide notification number S.O. 2895(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.785(E) dated the 5th July, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs. 2.91 crore plus a corpus fund of Rs. 2.00 crore to Rs.10.00 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore; vide notification number S.O. 249(E) dated the 15th February, 2007 the estimated cost was further enhanced from Rs.10.00 crore plus a corpus fund of Rs.2.00 crore to

Rs.34,23,86,748.00 including a corpus fund of Rs.2.00 crore and vide notification number S.O. 840(E) dated 25th March, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs. 34.23 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore to Rs. 64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore' to 'Rs.104.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost Rs.64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore' to 'Rs.104.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.862(E) dated the 12th December, 1997, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (2), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.64.28 crore including a corpus fund of Rs. 2 crore", the letters, figures and words "Rs.104.40 crore including a corpus fund of Rs.2 crore" shall be substituted'.

[No. 40/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 92(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1111(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ब्लाईंड पीपल्स एसोसिएशन, जगदीश चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015, गुजरात" द्वारा "नेत्रहीनों और विकलांगों के लिए व्यापक पुनर्वास, चिकित्सीय और मानव संसाधन विकास सेवाओं" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 2.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2394(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-2009 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे

बाद में दिनांक 27-12-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2885(अ) के तहत तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2011-12 2012-13 और 2013-14 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2394(अ) के तहत अनुमानित लागत को 2.50 करोड़ रु. से बढ़ाकर 6.00 करोड़ रु. कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 27-12-2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2885(अ) द्वारा 6.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 11.00 करोड़ रु. कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "ब्लाईंड पीपल्स एसोसिएशन, जगदीश चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "नेत्रहीनों और विकलांगों के लिए व्यापक पुनर्वास, चिकित्सीय और मानव संसाधन विकास सेवाओं" की परियोजना अथवा स्कीम को 11.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

[सं. 41/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 92(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1111(E) dated the 8th August, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Comprehensive rehabilitation, medical & human resource development services for the blind and disabled" by "Blind People's Association, Jagdish Chowk, Surdas Marg, Vastrapur, Ahmedabad - 380015, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.50 crore for a period of three years beginning with financial year 2005-2006;

which was extended vide notification number S.O. No.2394(E) Dated 3rd October, 2008 for a further period of three year beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 2885 dated 27/12/2011 for a period of three more financial years, i.e., 2011-12, 2012-13 & 2013-14;

And whereas by notification number 2394(E) dated the 3rd October, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs. 2.50 crore to Rs. 6.00 crore; and which was further enhanced vide notification number S.O. 2885 dated 27/12/2011 from Rs.6.00 crore to Rs.11.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Comprehensive rehabilitation, medical & human resource development services for the blind and disabled”, which is being carried out by “Blind People’s Association, Jagdish Chowk, Surdas Marg, Vastrapur, Ahmedabad – 380015 Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.11.00 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 41/2015 /F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 93(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं. का.आ. 602(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसायटी, दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दरियागंज, नई दिल्ली” द्वारा “अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1994-95 समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 17.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 2-2-1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 94(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1997-98 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की

अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 12-3-1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 200(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और अनुमानित लागत को भी 17.57 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 28-12-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1269(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 2-2-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 129(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 4-6-2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1299(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25-3-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 651(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17-10-2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3166(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 40.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 154.49 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना लागत को ‘40.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 154.49 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 12-8-1993 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 602(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित क्रम सं. (3), कॉलम (4) में, ‘40.00 करोड़ रुपये’ अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए ‘154.49 करोड़ रुपये’ अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 42/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 93(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroha, District Hisar, Haryana" by "Maharaja Agrasen Medical Education & Scientific Research Society, Dayanand Bhawan, 3/5, Asaf Ali Road, Darya Ganj, New Delhi", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.17.57 crore for a period of three years ending with Assessment year 1994-1995; which was extended further vide notification number S.O.94(E) dated the 2nd February, 1996 for a period of two years ending with assessment year 1997-1998; which was extended further vide notification number S.O.200(E) dated the 12th March, 1998 for a period of three years ending with assessment year 1999-2000 and the estimated cost was also enhanced from Rs.17.57 crore to Rs.40.00 crore; which was extended further vide notification number S.O.1269(E) dated the 28th December, 2001 for a period of three years ending with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.129(E) dated the 2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. No. 1299(E) dt.4.06.2008 for a period of three years beginning with the Financial Year 2007-08; which was extended further vide notification number S.O. 651(E) dated 25.03.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number 3166(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 40.00 crore to Rs. 154.49 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs. 40.00 crore to Rs. 154.49 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "40.00 crore", the letters, figures and words "Rs. 154.49 crore" shall be substituted'.

[No. 42/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 94(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19-12-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डिग्नटी फाउंडेशन (पंजीकृत), बीएमसी स्कूल बिल्डिंग टोपीवाला लेन, लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के सामने, ग्रांट रोड (पूर्व) मुंबई-400007, महाराष्ट्र" द्वारा "डिग्नटी डीमेंशिया डे केयर सेंटर" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 ककग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "डिग्नटी फाउंडेशन (पंजीकृत), बीएमसी स्कूल बिल्डिंग टोपीवाला लेन, लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के सामने, ग्रांट रोड (पूर्व) मुंबई-400007, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "डिग्नटी डीमेंशिया डे केयर सेंटर" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.80 करोड़ की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों से आगे तीन वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 43/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 94(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number '1' 'Dignity Dementia Day Care Centre' by "Dignity

Foundation(Regd.), BMC School Building, Topiwala Lane, Opposite Lamington Road Police Station, Grant Road (East), Mumbai-400007, Maharashtra”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.80 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project ‘Dignity Dementia Day Care Centre’ which is being carried out “Dignity Foundation(Regd.), BMC School Building, Topiwala Lane, Opposite Lamington Road Police Station, Grant Road (East), Mumbai-400007, Maharashtra”, without any change in the approved cost of Rs.1.80 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 43/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 95(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20-09-2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 901(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “फ्रैंड्स ऑफ द ट्राइबल सोसायटी, 19-गंगा प्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025” द्वारा “6 राज्यों में 2890 जनजातीय क्षेत्रों में एक अध्यापक स्कूल (ओटीएस) चलाने की साक्षरता परियोजना” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 867 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 05-07-2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 797(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 29-03-2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 478(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14-06-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1384(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 478(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 867 लाख रुपये से बढ़ाकर 1650 लाख रुपये कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 14-06-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1384(अ) द्वारा आगे संशोधित करके 1650 लाख रुपये से बढ़ाकर 5504.04 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत को 5504.40 लाख रुपये से बढ़कर 12630 लाख रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 5504.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 12630 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “फ्रैंड्स ऑफ द ट्राइबल सोसायटी, 19-गंगा प्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025” द्वारा चलाई जा रही “6 राज्यों में 2890 जनजातीय क्षेत्रों में एक अध्यापक स्कूल (ओटीएस) चलाने की साक्षरता परियोजना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और (ख) दिनांक 20 सितंबर, 2001 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 901(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित क्रम सं. (13), कॉलम (4) में, “5504.04 लाख रुपए” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए “12630 लाख रुपए” अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 44/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 95(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.901(E) dated the 20th

September, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for 'Literacy project of running 2890 One Teacher Schools (OTS) at 2890 tribal areas in 6 States', by "Friends of the Tribal Society, 19- Ganga Prasad Mukherjee Road, Kolkatta-700025", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 867 lakh for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.797(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.478(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide notification number 1384(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.478(E) dated the 29th March, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs. 867 lakh to Rs.1650 lakh; and which was further enhanced vide notification number 1384(E) dated 14.6.2011 from Rs.1650 lakh to Rs.5504.04 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 5504.40 lakh to 12630 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also amending the project cost from Rs. 5504.40 lakh to 12630 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby specifies the scheme or project for 'Literacy project of running 2890 One Teacher Schools (OTS) at 2890 tribal areas in 6 States', which is being carried out by "Friends of the Tribal Society, 19-Ganga Prasad Mukherjee Road, Kolkatta-700025", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number S.O.901(E) dated the 20th September, 2001, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 13, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters,

figures and word "Rs. 5504.04 lakh" the letters, figures and word "Rs. 12630 lakh" shall be substituted.

[No. 44/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 96(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14-12-1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 973(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सी-320, सेक्टर-19, नोएडा-201301" द्वारा "नोएडा में निशुल्क चिकित्सा सहायता सेवाएं चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 16-03-1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 212(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 10-09-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 982(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 03-02-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 141(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 22-03-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 649(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 12-08-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1873(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 212(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 40.00 लाख रु. से संशोधित 75.00 लाख रु. कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 16-07-2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1163(अ) द्वारा आगे संशोधित करके 75.00 लाख रु. से बढ़ाकर 1.50 लाख रु. कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा “कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सी-320, सेक्टर-19, नोएडा-201301” द्वारा चलाई जा रही “नोएडा में निशुल्क चिकित्सा सहायता सेवाएं चलाने” की परियोजना अथवा स्कीम को 1.50 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 45/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 96(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 973(E) dated the 14th December, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for “Running of free medical aid services at NOIDA” by “Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-19, NOIDA-201301”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 40.00 lakh for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O. 212(E) dated the 16th March, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O. 982(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O. 141(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O. 649(E) dated the 22nd March, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 1873(E) dated 12.8.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O.212(E) dated the 16th March, 1998 the estimated cost was amended from Rs.40.00 lakh to Rs.75.00 lakh; and which was further amend vide S.O.1163(E) dated 16.7.2007, the estimated cost was amended from Rs. 75.00 lakh to Rs.1.50 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the

said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for “Running of free medical aid services at NOIDA”, which is being carried out by “Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-19, NOIDA-201301”, without any change in the approved cost of Rs.1.50 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 45/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 97(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25-05-2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 708(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई-400049” द्वारा “दिल्ली में 50,000 स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 17 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 04 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1312(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14-06-2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1374(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1312(अ) के तहत अनुमानित लागत को ‘3.64 करोड़ रु.’ से बढ़ाकर ‘1073.11 लाख रु. कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 14-06-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1374(अ) द्वारा 1073.11 लाख रु. से बढ़ाकर 27.16 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के

उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई-400049” द्वारा चलाई जा रही “दिल्ली में 50,000 स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने” की परियोजना अथवा स्कीम को 27.16 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 46/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 97(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.708(E) dated the 25th May, 2005, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 17, “Providing mid-day meal to 50,000 school-students in Delhi” by “Iskcon Food Relief Foundation”, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai – 400049”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.64 crore for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O. 1312(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 1374(E) dated 14.6.2011 for three years ending with financial year 2013-14;

And whereas by notification number S.O. 1312(E) dated 4th June, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs.3.64 crore to Rs. 1073.11 lakh; and which was further enhanced vide notification number S.O. 1374(E) dated 14.6.2011 from Rs. 1073.11 lakh to Rs.27.16 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with

clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Providing mid-day meal to 50,000 school-students in Delhi”, which is being carried out by “Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai – 400049”, without any change in the approved cost of Rs. 27.16 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 46/2015/F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 98(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12-07-2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1649(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भील सेवा मंडल दाहोद, ठक्कर बापा रोड, दाहोद-389151, गुजरात” द्वारा “जनजातीय किसानों के लिए संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और कृषि सहायता, ऑर्गेनिक खेती, औषधीय और पशुचारा संबंधी पौधों का विकास, जनजातीय गांवों के लिए पेयजल, सिंचाई के कुओं और चेक बांधों का प्रावधान, जनजातीय छात्रावासों के लिए सुरक्षा दिवारों, जनजातीय बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाली अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है; चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 बीत चुका है इसलिए धारा 35 क ग के तहत उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “भील सेवा मंडल दाहोद, ठक्कर बापा रोड, दाहोद-389151, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “जनजातीय किसानों के लिए संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और कृषि सहायता, ऑर्गेनिक खेती, औषधीय और

पशुचारा संबंधी पौधों का विकास, जनजातीय गांवों के लिए पेयजल, सिंचाई के कुओं और चेक बांधों का प्रावधान, जनजातीय छात्रावासों के लिए सुरक्षा दिवारों, जनजातीय बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता” की परियोजना अथवा स्कीम को 1 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.11 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 47/2015/फा.सं. वी-27015/3/2014-एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 98(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1649(E) dated 12.7.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number ‘10’ ‘Resource management training and agricultural support, organic farming, development of medicinal and fodder plants for tribal farmers, provision for drinking water, irrigations wells and check dams for tribal villages, protection walls for tribal hostels, educational aids for tribal children’ by “Bhil Seva Mandal Dahod, Thakkar Bapa Road, Dahod 389151, Gujarat”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.9.11 crore including a corpus fund of Rs.1 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16. Since the financial year 2013-14 has already lapsed, no exemption under Section 35AC shall be available for the said financial year 2013-14.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Resource management training and agricultural support, organic farming, development of medicinal and fodder plants for tribal farmers, provision for drinking water, irrigations wells and check dams for tribal villages, protection walls for tribal hostels, educational aids for tribal children”, which is being carried out “Bhil Seva Mandal Dahod, Thakkar Bapa Road, Dahod 389151, Gujarat” without any change in the approved cost of Rs.9.11 crore including a corpus fund of Rs.1 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16.

[No. 47/2015 / F.No.V-27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy.
(National Committee)